

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 262 बेमेतरा, मंगलवार 19 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली से गुजरात तक पारा 40 डिग्री के पार, अंधड़-बारिश का भी अलर्ट

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में अंधड़-बारिश के बीच अब गर्मी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। लू का प्रकोप शुरू हो गया है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों में शनिवार को तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया और गर्मी से बचाव के लिए सड़कों पर पानी की फुहारें छोड़ी गईं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तर भारत में गर्मी और तेज होने के साथ अंधड़-बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत एनसीआर में 17 मई को भीषण गर्मी के साथ शाम के समय धूल भरी आंधी चलने, बिजली कड़कने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान राजधानी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके बाद आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ रहा है। बाढ़ों में तापमान 44.8 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं दक्षिण हिस्से में लू चलने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने सीकर, हनुमानगढ़, जालोर, सिरोही समेत 8 जिलों में लू का यलो अलर्ट जारी किया है।

तिरुवनंतपुरम-दिल्ली एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित

कोटा। तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस (12431) के एसी कोच में आज सुबह करीब 5 बजे आग लग गई। हादसा कोटा मंडल के विक्रमगढ़ आलोट (मध्य प्रदेश) स्टेशन के पास हुआ। लोकोपायलट और गार्ड की सूझबूझ के चलते सभी यात्रियों को कोच से बाहर निकाल लिया गया और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आग बी-1 कोच से शुरू हुई थी और 2 और डिब्बों में फैल गई। घटना तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के बी-1 कोच में हुई। रेलवे अधिकारियों ने कहा, प्रभावित कोच के सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। किसी भी यात्री या रेलवे कर्मचारी को चोट नहीं आई है।

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी मजबूती

शाह ने अत्याधुनिक डायल 112 और फारेंसिक वैन को दिखाई हरी झंडी

■ अब सभी 33 जिलों में लागू होगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अत्याधुनिक डायल 112 आपात सेवा

■ 400 नए आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन और 60 राजमार्ग गश्ती वाहन किए गए रवाना

रायपुर/ संवाददाता

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजधानी रायपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में छत्तीसगढ़ की 'अत्याधुनिक डायल 112' आपातकालीन सेवा तथा आधुनिक

फॉरेंसिक मोबाइल वैन के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य की आपातकालीन सहायता प्रणाली का विस्तार करना और नए आपराधिक कानूनों के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना है। वर्ष 2018 से संचालित डायल 112 आपात सेवा का दायरा बढ़ाते हुए इसे अब राज्य के सभी 33 जिलों में पूरी तरह लागू कर दिया गया है, जो पहले केवल 16 जिलों तक सीमित थी। इस नए और उन्नत चरण के तहत संपूर्ण व्यवस्था को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और



त्वरित बनाया गया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में पड़े व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सकेगा। इसके

साथ ही, आपातकालीन कॉल और ऑकड़ों का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए सिविल लाइंस स्थित प्राथमिक नियंत्रण केंद्र के अतिरिक्त नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में वैकल्पिक बैकअप प्रणाली पर आधारित दूसरा नियंत्रण केंद्र भी सक्रिय किया गया

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय का बेटा गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप

हैदराबाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी भगीरथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप हैं। हालांकि, भगीरथ की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए। बंदी संजय ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पुलिस को सौंपा है। वहीं, इस बयान के बाद पुलिस ने कहा कि आरोपी भगीरथ को हैदराबाद के बाहरी इलाके से पकड़ा गया है। बंदी संजय ने कहा, सत्यमेव जयते, कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए आज मेरा बेटा बंदी भगीरथ वकीलों के जरिए जांच के लिए तेलंगाना पुलिस के सामने गया।

वामपंथ के 10 साल के शासन को किया खत्म

केरल में वीडो सतीशन ने सीएम पद की ली शपथ..

नई दिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस नेता वीडो सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सेंट्रल स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरेगे भी मौजूद रहे। हाल ही में संपन्न हुए केरल विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शानदार जीत हासिल कर वामपंथ के दस साल के शासन को खत्म कर दिया है। आज वीडो सतीशन तिरुवनंतपुरम में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।



कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफकी शानदार जीत के बाद पार्टी ने वीडो सतीशन को इस पद के लिए चुना है। इसके साथ ही, केरल में एक लंबे अंतराल के बाद शीर्ष पद पर कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली नई

यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीडो सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें राज्यपाल आर.वी. अल्लेर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वीडो सतीशन के साथ उनके साथ पूरी 20 सदस्यीय कैबिनेट भी एक साथ शपथ ग्रहण कर रही। ये केरल में लगभग छह दशक बाद ऐसा मौका होगा, जब मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक साथ शपथ ले रहे हैं।

पालघर में भीषण सड़क हादसा

बारातियों से भरे ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत सड़क पर बिछ गई लाशें, मची चीख-पुकार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। धानीवरी क्षेत्र में बारातियों से भरे एक ट्रक और तेज रफ्तार कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर लाशें बिछ गईं। मौके पर अपरा-तप्परी मच गई और कई लोग ट्रक में ही फंस गए। रविवार को मुंबई-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में 12 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक में 100 से अधिक बाराती सवार थे, जो नाचते-गाते



एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में शादी की ये खुशियां चीख-पुकार और मातम में बदल जाएंगी। धानीवरी इलाके में पहुंचते ही सामने से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार

में भली कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया भी चल रही है। हादसा कैसे हुआ इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य और जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो से हादसे की भयावहता का पता लगाया जा सकता है।

आतंकवाद पर भी गरजे पीएम मोदी

100 बिलियन डॉलर निवेश और 10 लाख नौकरियां! नाँवें और भारत के बीच हुई बड़ी डील-पीएम मोदी...

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नाँवें की यात्रा पर हैं। यहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने नाँवें के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे से मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद दोनों देशों के नेताओं ने अपना संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि, नाँवें की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और मानवीय विकास के बीच हार्मनी का एक

सुंदर उदाहरण है। इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में खास है क्योंकि चार दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाँवें की यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कल नाँवें के संविधान दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से यहां की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पिछले साल नाँवें आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा हमें स्थगित करनी पड़ी थी। उस कठिन समय में नाँवें ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होकर सच्ची

मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नाँवें आया हूँ, तो मैं इस एकजुटता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, आज पूरी दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले साल भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन ने एक ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी लागू किया। पीएम मोदी ने कहा, यह समझौता भारत और नाँवें के बीच एक साझा विकास सुनिश्चित करने

के ब्लूप्रिंट है। इस समझौते में अगले 15 साल में भारत में 100 बिलियन डॉलर निवेश और 1 मिलियन नौकरी बनाने का लक्ष्य है। इस समझौते को परिणाम में बदलने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज हम भारत नाँवें संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साझेदारी से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलिएंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर ग्रीन शिपिंग तक हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नाँवें की तकनीक और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनियां ग्लोबल समाधान

निकालेंगी। रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत स्तंभ बने हैं। उन्होंने कहा, आज हमने सस्टेनिबिलिटी, ओसिएन एनर्जी, जियोलांजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल क्षेत्रों में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपनी पार्टनरशिप को फ्यूचर-रेडो बनाएंगे। स्किल डेवलपमेंट और मोबिलिटी में भी हमारा सहयोग और व्यापक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाँवें आर्कटिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत के आर्कटिक

हरिद्वार से भाग रहा था दिल्ली

सीएम शुभेंदु के पीए का हत्यारा गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक संयुक्त टीम ने उसे पकड़ा है। आरोपी राजकुमार उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। वह बलिया का रहने वाला है। सीबीआई ने उसके छपाट टोल प्लाजा हू। 58 हाइवे से हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक, हत्यारोपी राजकुमार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा के



रतोपुर सांवरा गांव का रहने वाला है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से ही उसका मोबाइल फोन रिवच ऑफ था। सीबीआई और बंगाल पुलिस की संयुक्त टीम फिलहाल कई और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है।



अधिकारी संयमित एवं संवेदनशील व्यवहार रखें, नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें, जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें - कलेक्टर

सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध निराकरण के लिए निर्देश

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने शासन के मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी निर्देशानुसार समय-सीमा बैठक की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। आज समय-सीमा बैठक में केवल जांजगीर-चांपा मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी ही जिला कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित रहें एवं शेष सभी अधिकारी, जिनमें जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने ब्लॉक मुख्यालय स्थित स्वान कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को वाहनों का उपयोग साझा व्यवस्था में करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की

रायकोना के रघुनाथ साहू और योगेश्वरी साहू ने की सादगी और गरिमापूर्ण विवाह

एक ही जाति के वर वधु ने अपने माता पिता की रजामंदी और उपस्थिति में की शादी, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कलेक्टर कोर्ट में सादगी से विवाह सम्पन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सह विवाह अधिकारी कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के समक्ष जिले के ग्राम रायकोना के वर रघुनाथ साहू और वधु योगेश्वरी साहू ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अपने अपने माता-पिता की

नहरपाली फीडर में बार-बार फॉल्ट से लोग परेशान, बिजली व्यवस्था पर उठे सवाल



नहरपाली/मूक पत्रिका

किरोडीमल नगर से जुड़े सिंघनपुर उप केंद्र अंतर्गत नहरपाली फीडर में लगातार आ रहे फॉल्ट से क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन बिजली बंद होने से घरेलू कार्य, खेती-किसानी और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नहरपाली फीडर में बार-बार



बैठकें भी यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने कहा गया है। कलेक्टर ने जिले में स्वीकृत एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की जानकारी अनिवार्य रूप से जिले की वेबसाइट एवं निर्माण पोर्टल पर नियमित अपलोड करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि कार्यों की सतत मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के मंशानुरूप सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपना आचरण एवं व्यवहार मर्यादित रखें तथा आम नागरिकों की समस्याओं और बातों को गंभीरता से सुनें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मूल उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना है और प्रत्येक अधिकारी को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने अधिकारियों को अपने दायित्वों के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा सुशासन तिहार के तहत नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान हेतु जिले में जनसमस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनसमस्या निवारण शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आमजनों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने शिविरों में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की एवं शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुचारु

वृद्ध महिला हत्या कांड का 24 घंटे में खुलासा, धरमजयगढ़ पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार, आरोपी ने मां की हत्या की बीच-बचाव करने आई बेटी पर भी किया जानलेवा हमला

आरोपी से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा बरामद, आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

घरेलू हिंसा और हत्या जैसे अपराधों पर रायगढ़ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति— एसएसपी शशि मोहन सिंह

धरमजयगढ़/मूक पत्रिका

थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिकटवानी मुड़ाडीपा में 70 वर्षीय वृद्ध महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले में धरमजयगढ़ पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण का खुलासा कर दिया। कल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम चिकटवानी मुड़ाडीपा निवासी श्रीमती मेरीना



लकड़ (70 वर्ष) अपने घर में खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक राजेश जांगड़े टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां मृतिका के सिर, माथे और कान के ऊपर गंभीर चोट के निशान मिले। साथ ही मृतिका की नातिन ओगीटिना लकड़ (10 वर्ष) भी सिर में गंभीर

चोट लगने से बेहोश हालत में मिली, जिसे पुलिसकर्मियों एवं ग्रामीणों की मदद से तत्काल एंबुलेंस द्वारा उपचार हेतु सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना धरमजयगढ़ में अपराध क्रमांक 140/2026 धारा 103(1),109 ब्रह्म दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान संदेह मृतिका के बेटे संदीप लकड़ा पर गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्काल ग्राम चिकटवानी मुड़ाडीपा पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। पृष्ठताछ में आरोपी संदीप लकड़ा पिता स्व. भीमा लकड़ा उम्र 37 वर्ष ने अपराध स्वीकार करते

हुए बताया कि वह ड्रायवरी का काम करता है। 05 बच्चे हैं जिसमें 03 लड़की एवं 02 लड़का हैं। इसकी लड़की क्रिटीवा का एक्सीडेंट में पैर टूटा था उसकी ईलाज करवाने में मेरी पति, बेटी अगस्टीना लकड़ा, छोटा लड़का मनजीत लकड़ा और लड़की सेरेस्टिना के साथ दिनांक 11.05.2026 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ गये थे। वहीं रूक कर ईलाज करवा रहे थे। दिनांक 14.05.2026 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से आयुष्मान कार्ड लेने तथा खाना बनाने के बर्तन एवं कम्बल लेने के लिये लड़की अगस्टीना के साथ बस में बैठकर रायगढ़ से धरमजयगढ़ आया। आरोपी तब से गांव में घूम घूम कर शराब पी रहा था

जिसे उसकी मां मेरीना लकड़ा शराब पीने के लिये मना कि और डांटी एवं बोली कि मतवारी कर रहे हो तब मैं घर से निकलकर बस्ती तरफ आ गया और फिर शराब पीकर आया फिर आक्रोशित होकर घर में रखे डंडा से अपनी माँ को सिर एवं कान के नीचे को ताबड़ तोड़ मारपीट कर रहा था उसी समय बेटी अगस्टीना बीच बचाव करने के लिये आई उसे भी जान से मारने की नियत से सिर में मारा। लकड़ी अगस्टीना अपनी जान बचाकर दूसरे घर में चली गई। आरोपी के मेमोरैंडम पर घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डंडा को जब्त किया गया। आरोपी को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

कटंगपाली पेट्रोल पंप में व्यवस्था संभालने खुद मैदान में उतरे संचालक, लंबी कतारों के बीच नियमों के तहत बांटा जा रहा डीजल..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले में डीजल की कमी और बढ़ती मांग के बीच कटंगपाली पेट्रोल पंप में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रक, चारपहिया और बाइक लेकर बड़ी संख्या में लोग डीजल-पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं। लगातार बढ़ती भीड़ और लंबी कतारों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब खुद पेट्रोल पंप संचालक धीरज अग्रवाल अपने भाई नीरज अग्रवाल के साथ मैदान में उतर गए हैं।

सुबह से लग रही वाहनों की लंबी लाइन-कटंगपाली स्थित पेट्रोल पंप में इन दिनों सुबह से ही वाहनों की लंबी कतार लग जा रही है। खेती-किसानी का सीजन होने के कारण किसानों को ट्रैक्टर और हार्वेस्टर चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ रही है। वहीं परिवहन और व्यावसायिक कार्यों से जुड़े वाहन चालक भी डीजल के लिए पंप पहुंच रहे हैं।स्थिति यह है कि



डीजल आने की खबर मिलते ही आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पंप परिसर में अफा-तफरी जैसे हालात बनने लगते हैं।

व्यवस्था सुधारने खुद मोर्चा संभाले पंप संचालक-भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए पंप संचालक खुद अपने भाई के साथ पूरी व्यवस्था संभालते नजर आ रहे हैं। दोनों भाई लाइन व्यवस्थित कराने, वाहनों को क्रम से खड़ा कराने और तय सीमा के अनुसार डीजल वितरण कराने में जुटे हुए हैं। पंप में शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सीमित मात्रा में डीजल दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से

ज्यादा लोगों तक डीजल पहुंच सके और किसी का काम पूरी तरह प्रभावित न हो।

किसानों और वाहन चालकों को मिल रही राहत-पेट्रोल पंप में व्यवस्था बेहतर होने से किसानों और वाहन चालकों को कुछ राहत मिल रही है। पहले जहां अव्यवस्था के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब लाइन के अनुसार डीजल मिलने से स्थिति काफी हद तक नियंत्रित नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि डीजल संकट के बीच यदि इसी तरह व्यवस्थित वितरण होता रहा तो लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रशासन के निर्देशों का पालन जारी-जिले में डीजल संकट को देखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को तय सीमा में ही डीजल वितरण करने के निर्देश दिए हैं। कटंगपाली पेट्रोल पंप में भी इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए जरूरतमंदों को नियमित रूप से डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से किया लाभान्वित, मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान की घोषणा

जनसमस्या निवारण शिविर में पहुँचे कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल

नागरिकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने तथा आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक दयाल दास बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं नागरिकों ने अपनी समस्याएं, मांगें और शिकायतें मंत्री श्री बघेल के समक्ष रखीं। मंत्री श्री बघेल ने सभी आवेदनों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार



पर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए।

समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं-शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जन समस्या निवारण

शिविर केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास एवं संवाद का सशक्त माध्यम है।उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आवेदनों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों और मांगों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा वे स्वयं करेंगे। मंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनते हुए उनका व्यवहारिक एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।



शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को मिला लाभ-मंत्री श्री बघेल ने कहा कि जन समस्या निवारण शिविर केवल आवेदन लेने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित कर शासन की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का परिचय देना चाहिए।इसी कड़ी में शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को डिजिटल किसान किताब प्रदान की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 बालिकाओं को

नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीजन प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत 5 मरीजों को निश्चय किट प्रदान की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास पूर्ण होने पर 3 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर उन्हें गृह प्रवेश की शुभकामनाएं दी गईं। शिविर में हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी और संतोष स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की घोषणा-मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने की घोषणा भी की। उन्होंने क्षेत्र के कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने की बात कही। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कक्षा 12वीं के 16 मेधावी छात्र-छात्राओं को 10-10 हजार रुपए तथा कक्षा 10वीं के 8 छात्र-छात्राओं को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियां पूरे क्षेत्र के

लिए गौरव का विषय हैं तथा ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

ग्रामीण समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश-मंत्री श्री बघेल ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि ऐसे आवेदन जिनका निराकरण मौके पर संभव नहीं हो पाया है, उन पर तत्काल वास्तविक कार्रवाई प्रारंभ कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आवेदनों की जांच पूर्ण कर आवेदकों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं एवं राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई, विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं नागरिक उपस्थित रहे।

संपादकीय

पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने एक बार फिर यही दर्शाया कि मौसम की मार से बचाव के लिए एहतियात बरतने से लेकर सटीक पूर्वानुमान को लेकर तकनीकी स्तर पर अभी बहुत कुछ किए

जाने की जरूरत है। राज्य के कई इलाकों में बुधवार की शाम को तेज आंधी-तूफान, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि एक तरह से कहर बरपा रही थी और आम लोग उसके सामने लाचार थे।कई जगहों पर तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। कितनी ही जगहों पर भारी पेड़ उखड़कर वाहनों पर गिर गए और सड़कों के किनारे लगे बोर्ड उड़कर तेज रफ्तार से जमीन पर गिरे। करीब चौबीस घंटों के दौरान करीब सौ लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग

घायल हो गए। कई जिलों में दो हजार से ज्यादा गांवों में बिजली गुल हो गई। कूदरत के इस कहर के बाद मौसम विभाग ने राज्य के अड़तीस जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर पीली चेतावनी जारी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूर्वानुमानों के बावजूद कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिनमें तूफान या बिजली गिरने की घटनाएं आम लोगों पर कहर बनकर टूटती हैं।जाहिर है, मौसम की अपनी गति होती है और प्रकृति में उथल-

पुथल के नतीजे में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष अचानक मौसम का रुख बिगड़ने की आशंका के बावजूद आम लोग इससे बचाव के लिए एहतियात नहीं बरत पाते। इसका खमियाजा यह सामने आता है कि जिन हालात में कुछ लोगों की जान बच सकती थी, उसमें नाहक ही कई लोगों की जान चली जाती है।राज्य में मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती ढांचे और दक्षिण राजस्थान से आ रही

हवाओं के प्रभाव से वहां कई जगहों पर अस्सी से सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। नतीजतन, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। कई जगहों पर न केवल घरों की छत उड़ गई, बल्कि लोगों के लिए पांव टिकाना भी मुश्किल था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे मौसम में बचाव को लेकर जरूरी प्रशिक्षण के अभाव का नुकसान आम लोगों को किस स्तर पर उठाना पड़ता है।संभव है कि पश्चिमी विश्वो को के कमजोर पड़ने के साथ-साथ मौसम साफ होने

लगे और उसके बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो, लेकिन इसके साथ यह भी सच्चाई है कि साल के इन महीनों में कई बार तेज रफ्तार से चलने वाला तूफान और ओलावृष्टि कई स्तर पर आम लोगों के लिए व्यापक क्षति और खतरे का वाहक बनते हैं।पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है।

सत्ता संभालते ही हिंदुत्व माॉडल के जरिये बंगाल में बड़े बदलाव कर रहें सुवेंदु अधिकारी

(नीरज कुमार दुबे)

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता की कमान संभालते ही चुनावी वादों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाने तो शुरू कर ही दिये हैं साथ ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में तेज बदलावों का दौर भी शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें राज्य की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को उनके गढ़ में पराजित कर सत्ता तक पहुंचे सुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के केवल 48 घंटे के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन बड़े निर्णयों की घोषणा कर यह संकेत दे दिया कि नई सरकार प्रशासनिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर व्यापक बदलाव चाहती है।

नई सरकार के शुरुआती फैसलों में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सख्ती प्रमुख रही। सरकार ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा धार्मिक गतिविधियां निर्धारित परिसरों तक सीमित रहेंगी। कोलकाता के रेड रोड क्षेत्र में सार्वजनिक नमाज पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी नियंत्रण लगाया गया है। सरकार ने पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

साथ ही सुवेंदु अधिकारी सरकार ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2023 के पंचायत चुनावों के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। इन मामलों को पिछली सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित और बंद मामलों की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है।

इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों को भी दोबारा जांच के दायरे में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पंद्रह वर्षों में मारे गए तीन सौ इक्कीस भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार यदि चाहें तो सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी। यह फैसला राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर भाजपा के लंबे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

इसके अलावा, नई सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई करने और पुलिस को बिना राजनीतिक दबाव के काम करने की खुली छूट देने की घोषणा की है। प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और किसी की राजनीतिक पहचान को महत्व न दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि कानून व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाएगा।

साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के मुद्दे पर भी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य में अवैध पशु बाजारों को बंद करने और अवैध परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर चौबीस पराना जिलों में चल रहे अवैध पशु बाजारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को पैतालीस दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अवैध घुसपैठ और जनसंख्या

संतुलन में हो रहे बदलावों पर रोक लगेगी।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य में पशु वध को लेकर भी सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब किसी भी पशु के वध से पहले उसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र नगर निकाय प्रमुख और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त सहमति से जारी किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही इसकी अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर छह महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। नई सरकार के इस कदम को कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

साथ ही राज्य में लंबे समय से चर्चा में रहे सिंडिकेट राज और अवैध खनन पर भी सरकार ने कार्रवाई का संकेत दिया है। जिला और प्रखंड स्तर पर सक्रिय कथित सिंडिकेट नेटवर्क को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि पिछली व्यवस्था में निर्माण सामग्री और कई क्षेत्रों में प्रभावशाली समूहों का नियंत्रण



था, जिसे खत्म करना आवश्यक है।

सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव करते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की सुरक्षा हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस शासनकाल में विभिन्न बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों और गैर वैधानिक संस्थाओं में नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। साठ वर्ष से अधिक आयु वाले अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। नई सरकार ने केंद्र की कई योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना, विश्वकर्म योजना और उज्ज्वला योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को केंद्र सरकार के साथ आवश्यक समझौते तेजी से पूरा करने को कहा है। साथ ही राज्य की नई भाजपा सरकार ने शिक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े मोर्चे पर भी बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के

कार्य करेगी।

इसके अलावा, प्रशासनिक ढांचे में सुधार की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस अधिकारियों को केंद्र सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर के मानकों से जोड़ना है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के आठ अधिकारियों ने नई दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसे पश्चिम बंगाल की नौकरशाही में बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत माना जा रहा है। बहरहाल, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुवेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व आधारित राजनीति को जमीन पर उतारने की दिशा में तेज कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर सख्ती, वंदे मातरम् को अनिवार्य करना, सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जैसे फैसलों को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के ‘दिल्ली-विमर्श’ के निहितार्थ

(कमलेश पांडे)

देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चों पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान और यूएई सीधे तौर पर इस हलचल में शामिल हैं। ऐसे में यह जुटान पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाती है।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय दिल्ली बैठक ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संदेश दिए हैं, जिनके कूटनीतिक निहितार्थ को समझने की जरूरत है। अन्यथा शेष दुनिया को अमेरिकी-यूरोपीय दादागिरी (नाटो सैन्य गठबंधन) के दुनियावी दांवपेंचों से निजात मिलनी मुश्किल है। लिहाजा, इस बैठक में मुख्य रूप से वैश्विक शक्ति-संतुलन, अमेरिकी प्रतिबंध नीति, पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक व्यापार व्यवस्था और ‘ग्लोबल साउथ’ की भूमिका पर जोर दिखाई दिया।

देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चों पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगघची जैसे नेताओं के दूरदर्शिता भरे बयान विशेष चर्चा में रहे। जिसके दुनियावी मायने बेहद अहम हैं। जिस तरह से कूटनीतिक सम्मेलन के पहले ही दिन जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो सबसे ज्यादा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनका इशारा

अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, ईरान मामले में भी गतिरोध की वजह बहुत हद तक वॉशिंगटन की अव्यवहारिक मांगें हैं। ब्रिक्स के बड़े मंच से उठी आवाज का असर ज्यादा होगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर का उद्घाटन भाषण मौजूदा चुनौतियों का सही खाका खींचता है। पश्चिम एशिया पर मंडराता युद्ध का खतरा, ऊर्जा संकट, स्पलाई चैन में रुकावट और जलवायु परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी में फंंसने का डर सता रहा है। ऐसे में जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, विकासशील देशों ने ब्रिक्स से यह उम्मीद लगाई है कि यह मंच स्थिरता कायम करने में सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। इसके कतिपय निहितार्थ इस प्रकार हैं-

पहला, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती-बैठक का सबसे बड़ा संदेश यह था कि दुनिया अब केवल अमेरिका-केंद्रित व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ब्रिक्स देशों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड के दृष्टिगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि वैश्विक निर्णयों में पश्चिमी देशों के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की शक्तियों की भी बराबर भूमिका हो।

दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का विरोध-भारत, रूस, चीन और ईरान सहित कई देशों ने एकतरफा प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संप्रभुता के खिलाफ बताया। विशेष रूप से एस जयशंकर ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव कूटनीति का

विकल्प नहीं हो सकते। यह संदेश सीधे तौर पर अमेरिका की प्रतिबंध नीति की आलोचना माना गया।

तीसरा, डॉलर प्रभुत्व कम करने का संकेत- बैठक में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। यह संदेश था कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं



ताकि अमेरिकी आर्थिक दबाव का असर घटाया जा सके।

चतुर्थ, पश्चिम एशिया संकट पर चिंता- ईरान-इज़राइल तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा। ब्रिक्स देशों ने रेड सी और होर्मुज् जलडमरूमध्य जैसे मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि क्षेत्रीय युद्ध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस मंच के सामने भी चुनौती है। ईरान और

यूएई के आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। जबकि चीन ने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा है।

एक बात और, जब सम्मेलन की शुरुआत हुई, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तब ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त थे। ब्रिक्स के सबसे बड़े विरोधी ट्रंप है। उन्हें लगता है कि यह मंच अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़ा किया



गया है। मेजबान होने के नाते यह भारत की जिम्मेदारी है कि यहां से निकला संदेश किसी की विरोध में नहीं, साझा हित में हो। भारत के पास सभी सदस्यों को करीब लाने और मौजूदा संकट का समाधान पेश करने का मौका है।

पांचवां, ग्लोबल साउथ की राजनीतिक आवाज-बैठक में यह स्पष्ट हुआ किब्रिक्स स्वयं को केवल आर्थिक समूह नहीं, बल्कि विकासशील देशों की सामूहिक राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। अफ्रीका,

एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की समस्याओं—जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और कर्ज—को वैश्विक एजेंडा में प्रमुखता देने की बात कही गई। छठा, संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग- भारत और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता दोहराई। यह संदेश था किद्वितीय विश्व युद्धके बाद बनी संस्थाओं में अब नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार बदलाव होना चाहिए।सातवां, ब्रिक्स के भीतर मतभेद भी सामने आए- हलांकि बैठक में एकजुटता दिखाई गई, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि सभी सदस्य अमेरिका-विरोधी नीति पर पूरी तरह एकमत नहीं हैं। भारत और ब्राजील जैसे देश पश्चिम के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि रूस और ईरान अधिक आक्रामक रुख चाहते हैं। इससे यह संकेत मिला कि ब्रिक्स अभी पूर्ण राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि साझा हितों वाला मंच है। समग्र रूप से कहा जाए तो, इस बैठक का वैश्विक संदेश यह था कि उभरती शक्तियां अब विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक स्वतंत्र, संतुलित और पश्चिम से अलग भूमिका चाहती हैं। ब्रिक्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि ग्लोबल साउथ अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का सक्रिय खिलाड़ी बनना चाहता है। चूंकि ब्रिक्स अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह नहीं रहा, इसकी भूमिका आज कहीं ज्यादा व्यापक हो चुकी है। वास्तव में यह वैश्विक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का रोल इसमें सबसे अहम हो जाता है। उसने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, जबकि रूस, ईरान और चीन के साथ भी बैलेंस रखा है। उसने हमेशा संवाद से समाधान की बात की है। यह रवैया उसे भरोसेमंद साथी बनाता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक हैं) । (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

कांगो और युगांडा में इबोला वायरस का कहर, डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल किया घोषित

अबुजा, एजेंसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेंडीस



अधानोम घेब्रेयसस ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह घोषणा रविवार, 17 मई 2026 को 300 से अधिक सदिग्ध मामलों और 88 मौतों के बाद की गई। डब्ल्यूएचओ ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि यह प्रकोप बुंडिबुगो वायरस के कारण हुआ है। संगठन ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति कोविड-19 महामारी जैसी नहीं है। यह प्रकोप महामारी आपातकाल के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। डब्ल्यूएचओ ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य अनावश्यक यात्रा और व्यापार प्रतिबंधों से बचना है। संगठन ने प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इबोला एक गंभीर और अवसर घातक बीमारी है। यह वायरस संक्रमित जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, उल्टी और आंतरिक रक्तस्राव शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ ने संक्रमण को रोकने के लिए सख्त उपायों की सिफारिश की है। इसमें स्वच्छता और संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना शामिल है।

राष्ट्रपति चुनाव से पहले कोलंबिया में हिंसा, पूर्व मेयर और उनके सहयोगी की गोली मारकर हत्या

बोगोटा, एजेंसी। कोलंबिया के मध्य इलाके में एक पूर्व मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी। इस हमले में पूर्व



मेयर रोजर्स डेविया के साथ उनके एक सहायक एडर कार्डाॅना की भी मौत हो गई। डेविया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अबेलाडों दी ला एस्पिएला के करीबी सहयोगी थे। एस्पिएला नेशनल साल्वेशन मूवमेंट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यह हमला कुबुरल के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। रोजर्स डेविया ने साल 2020 से 2023 के बीच इस शहर के मेयर के रूप में शासन किया था। कुबुरल शहर राजधानी बोगोटा से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मेटा विभाग के लोकपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस हमले की जानकारी साझा की। यह क्षेत्र वर्तमान में तीन सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। इनमें से दो समूहों को अमेरिकी सरकार ने आतंकवादी संगठन माना है। तीसरा समूह पूर्व विद्रोही संगठन 'फाक' से अलग होकर बना एक गुट है। लोकपाल कार्यालय का कहना है कि इस तरह की हिंसा से 31 मई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में लोगों के राजनीतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी पर बुरा असर पड़ सकता है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में कम से कम छह उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें दो सदस्य छोटी वामपंथी पार्टियों से हैं। चुनाव के नियमों के अनुसार, यदि किसी भी उम्मीदवार को कुल वोटों का 50 प्रतिशत हिस्सा नहीं मिलता है, तो जून में शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दोबारा मतदान कराया जाएगा। कोलंबिया के गृह मंत्री अरमांडो बेनेडेट्टी ने सोशल मीडिया पर कहा कि जांच अधिकारी अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि डेविया पर हमला क्यों किया गया। वालेंसिया के एक कमचारी पर होना वाले हमलों को नाकाम किया था। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

मालदीव में इटली के पांच गोताखोरों की मौत, दो दिन बाद भी एक ही शव हो सका बरामद

रोम, एजेंसी। मालदीव में एक गुफा के अंदर स्कूबा डाइविंग के दौरान इटली के पांच गोताखोरों की मौत के बाद शुक्रवार को भी खोज अभियान जारी रहा। इस अभियान में इटली के एक विशेषज्ञ भी पुलिस गोताखोरों और बचाव नौकाओं के समूह में शामिल हुआ। इटली के पांच नागरिकों की मौत गुरुवार को हुई थी, इसके बाद से ही बचाव अभियान और जांच तेज हो गई है। इटली के विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये पांचों गोताखोर कथित तौर पर गुरुवार को 50 मीटर (164 फीट) की गहराई पर गुफाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, जब यह

तकनीक, शिक्षा, सेहत और खनिज: नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी की मौजूदगी में 17 बड़े फैसले; सेमीकंडक्टर पर भी साझेदारी

एमस्टर्डम, एजेंसी। भारत और नीदरलैंड के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 17 बड़े समझौते और साझेदारियां हुईं। इन समझौतों का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक, शिक्षा, ऊर्जा, खेती, सेहत, डेयरी, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोनों देशों ने साफ कहा कि ये फैसले आने वाले समय में विकास, रोजगार, निवेश और वैश्विक सहयोग को नई दिशा देंगे।

भारत और नीदरलैंड ने 2026-2030 रणनीतिक साझेदारी रोडमैप तैयार किया है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इससे भारत को नई तकनीक, रोजगार और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। रक्षा, साइबर सुरक्षा और सप्लाय चैन पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। नीदरलैंड ने चोल काल की ऐतिहासिक तांबे की पट्टिकाएं भारत लौटाने पर सहमति दी। इससे भारतीय इतिहास और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। रिसर्च और संग्रहालयों को भी फायदा होगा। भारत और नीदरलैंड के

बीच वीजा प्रक्रिया आसान बनाने पर सहमति बनी। इससे भारतीय छात्रों, प्रोफेशनल्स और कामगारों को पढ़ाई और



नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे। इंटरशिप और लंबी अवधि के वीजा में भी सहूलियत मिलेगी। दोनों देशों के विश्वविद्यालय अब संयुक्त रिसर्च और डिग्री कार्यक्रम चला सकेंगे। भारतीय छात्रों और शिक्षकों को डच यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और रिसर्च के नए मौके

ब्रिटेन का संग्रहालय जैन समुदाय को लौटाएगा 2000 दुर्लभ पांडुलिपियां

वॉशिंगटन, एजेंसी। ब्रिटेन से भारत और जैन समुदाय के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है। लंदन के प्रमुख संग्रहालयों में शुमार वेलकम कलेक्शन ने एक सदी से भी अधिक समय से अपने पास रखी जैन धर्म की 2,000 से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियों को वापस लौटाने का एक बड़ा फैसला लिया है।

यह ऐतिहासिक फैसला इंस्टीट्यूट ऑफ जैनेोलॉजी के साथ लंबे संवाद और आपसी सहयोग के बाद लिया गया है। यह दक्षिण एशिया के बाहर मौजूद जैन पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है। इस बड़े कदम से जैन समुदाय को अपनी पुरानी और मूल्यवान धरोहर वापस मिल रही है।

क्या है इन दुर्लभ पांडुलिपियों का इतिहास और महत्व?

लंदन से वापस लौटाई जा रही इन 2000 पांडुलिपियों का इतिहास 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस विशाल संग्रह में धर्म, साहित्य, चिकित्सा और संस्कृति से जुड़ी कई दुर्लभ सामग्री शामिल है। ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राकृत, संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी और प्रारंभिक हिंदी जैसी प्राचीन लिपियों में सुरक्षित रखे गए हैं। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से इसका क्या संबंध है? इस ख़ास संग्रह में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नैतिक सिद्धांतों का एक बहुत ही प्रारंभिक और प्रभावशाली उदाहरण भी मौजूद है। यह वही सिद्धांत हैं जिनसे महात्मा गांधी ने प्रेरणा ली थी और बाद में उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया था। इस पुराने दस्तावेज में भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियाद की बहुत ही तीखी

आलोचना की गई है। इन हजारों दस्तावेजों के बीच साल 1688 की एक बहुत ही पतली,



नाजुक और जर्जर कागजी पांडुलिपि भी संग्रह में मिली है। इस पांडुलिपि को प्रारंभिक हिंदी के सबसे पहले चिकित्सा ग्रंथ 'वैद्य मनोत्सव' (1592) की सबसे पुरानी सुरक्षित प्रति माना जाता है। यह चिकित्सा के इतिहास के लिहाज से एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। इस ऐतिहासिक वापसी को लेकर कई अहम कदम उठाए गए हैं। इस सप्ताह वेलकम ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ जैनेोलॉजी और बर्मिंघम विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज़ापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस विशाल संग्रह को प्रारंभिक रूप से बर्मिंघम विश्वविद्यालय में स्थित 'धर्मनाथ नेटवर्क इन जैन स्टडीज' के पास सुरक्षित रखा

जाएगा। यहां शोधकर्ताओं और जैन समुदाय के लोगों को इन प्राचीन पांडुलिपियों का गहराई से

अध्ययन करने की पूरी सुविधा मिलेगी। इन ऐतिहासिक ग्रंथों की व्याख्या की जाएगी और लोगों के समझने के लिए इनका आसान भाषा में अनुवाद भी किया जाएगा। इन दुर्लभ और पवित्र पांडुलिपियों की वापसी से जैन समुदाय में काफी खुशी है। इंस्टीट्यूट ऑफ जैनेोलॉजी के प्रबंध न्यासी मेहुल संघराजका ने इस कदम का खुले दिल से स्वागत किया है। इस साहसिक निर्णय को बेहद ऐतिहासिक बताया है। मेहुल संघराजका का मानना है कि 2,000 पवित्र ग्रंथों को लौटाने का यह कदम केवल जैन समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य सभी धार्मिक समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श है।

इराक में अली अल-जैदी सरकार: यूएस-ईयू से लेकर ईरान-तुर्किये में कैसा माहौल

तेहरान, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इराक के नए प्रधानमंत्री अली फलिह काजिम अल-जैदी को पद संभालने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इराक के बीच लंबे समय से मजबूत और दोस्ताना संबंध रहे हैं और भारत इन रिश्तों को हर क्षेत्र में और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों की साझा तरक्की और समृद्धि के लिए नए इराकी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत इराक के साथ अपने पुराने और मजबूत संबंधों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, निवेश और कूटनीतिक सहयोग आने वाले समय में और मजबूत होगा। सीरिया के लिए विशेष दूत टॉम बैरक ने भी इराक के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका इराक में नए नेतृत्व का स्वागत करता है और दोनों देशों के साझा हितों पर मिलकर काम करना चाहता है। अमेरिका

चाहता है कि इराक एक मजबूत, स्थिर और समृद्ध देश बने, जो अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति बनाए रखे और अपने नागरिकों को बेहतर अवसर दे। टॉम बैरक ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका की सरकार इराक के साथ आतंकवाद खत्म करने और आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। इराकी संसद ने 14 मई को अली अल-जैदी की सरकार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में हथियारों पर सिर्फ सरकार का अधिकार होना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका लगातार इराक पर दबाव बना रहा है कि वह ईरान समर्थित हथियारबंद गुटों को कमजोर करे और उन्हें निस्स्त्र करे। संयुक्त राष्ट्र ने भी नई सरकार के गठन का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि यूएन इराक के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग जारी रखेगा।

नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच ऊर्जा परियोजनाएं...

ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा और नई तकनीक पर संयुक्त परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इससे निवेश और उद्योगों को फायदा मिलेगा। किसानों, डेयरी और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या बदलेगा?

कल्पसर परियोजना में तकनीकी सहयोग... गुजरात की बड़ी जल परियोजना में नीदरलैंड तकनीकी मदद देगा। इससे पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ सकती है।

फ्लावर सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, त्रिपुरा... फूलों की खेती को आधुनिक तकनीक मिलेगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

बंगलूरू में इंडो-डच डेयरी सेंटर... डेयरी किसानों और पशुपालन क्षेत्र को नई तकनीक और प्रशिक्षण मिलेगा। इससे दूध उत्पादन और गुणवत्ता सुधरेगी।

पशुपालन और डेयरी सहयोग... भारतीय पशुपालन क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बीमारी नियंत्रण और स्किल ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग... सार्वजनिक स्वास्थ्य, मेडिकल रिसर्च और वैज्ञानिक जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया। भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में यह सहयोग मदद करेगा। सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यह समझौता हुआ। इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी। दोनों देशों ने निवेश, हरित विकास, खाद्य सुरक्षा, जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति दी। तराई-मधेश क्षेत्र में लोगों का गुस्सा क्यों भड़क रहा था? इस नए नियम के लागू होने के बाद नेपाल-भारत सीमा पर तराई-मधेश क्षेत्र की चौकियों पर बहुत कड़ी जांच शुरू हो गई थी। सीमा शुल्क वसूलने के इस अनिवार्य नियम के कारण सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) ने आम लोगों की सघन तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। पहले आम नागरिकों को छोटी-मोटी रोजगारों की खरीदारी और घरेलू सामानों पर अनौपचारिक रूप से सीमा शुल्क में झूट मिल जाती थी।

होर्मुज में जहाजों पर हमले और आवाजाही बाधित करना अस्वीकार्य, संयुक्त राष्ट्र में भारत की खरी-खरी

न्यूयॉर्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा और उर्वरक संकट पर भारत का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा और आवाजाही की स्वतंत्रता में बाधाओं पर चिंता जताई। हरीश ने वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने और नागरिक चालक दल को खतरे में डालने को अस्वीकार्य बताया। साथ ही भारत ने जोर देकर कहा कि सुरक्षित समुद्री मार्गों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन होना चाहिए।

बता दें कि, पी. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा और आपूर्ति प्रवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा कि संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अल्पकालिक और संरचनात्मक उपाय आवश्यक हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरीश ने 'एक्स' पर लिखा कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए।

ईरान का नया समुद्री तंत्र: ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को विनियमित करने के लिए एक पेशेवर तंत्र की घोषणा की है। ईरानी संसद के एनएससी प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने 'एक्स' पर बताया कि यह तंत्र जल्द ही अनावरण होगा। इसे ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस तंत्र से केवल ईरान के साथ सहयोग करने वाले वाणिज्यिक जहाजों को लाभ मिलेगा। यह मार्ग 'स्वतंत्रता परियोजना' से जुड़े ऑपरेटरों के लिए बंद रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि

पश्चिम एशिया संकट को समाप्त करने के लिए शांति समझौता नहीं हुआ तो बहुत बुरा समय आएगा। इस बीच, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में शांति का प्राथमिक अवरोधक है। अराघची ने दावा किया कि 40 दिनों के युद्ध के बाद अमेरिका ने बातचीत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान में



इस कदम पर गहरा संदेह है। अराघची ने अमेरिकियों पर अविश्वास व्यक्त किया और इसे किसी भी कूटनीतिक प्रयास में मुख्य बाधा बताया। ओमान तट पर भारतीय जहाज पर हमला दरअसल, कुछ दिन पहले ओमान तट के पास भारत के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ था। यह जहाज सोमालिया से खाना हुआ था। ओमान की अधिकारियों ने जहाज पर मौजूद सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन हमला किसने किया, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यह ओमान के पास स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया की करीब 20 प्रतिशत ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया के तेल और गैस बाजार पर असर डाल सकता है। पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं।

ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका? ट्रंप के पोस्ट से पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव



को अभी भी वॉशिंगटन की नीयत पर भरोसा नहीं है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि ईरान की 14 सूत्रीय शांति योजना के अलावा कोई भी प्रस्ताव बेनतीजा साबित होगा। पश्चिम एशिया में तनाव का सबसे बड़ा केंद्र फिलहाल होर्मुज जलडमरूमध्य बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20 प्रतिशत वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। ईरान ने यहां शिपिंग कंट्रोल के लिए नया प्रस्ताव भी दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि कुछ समुद्री रास्तों को सीमित किया जा सकता है, जबकि ईरान के साथ सहयोग करने वाले व्यावसायिक जहाजों को नियंत्रित तरीके से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि पिछले महीने युद्धविराम की घोषणा हुई थी, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी मजबूत कर रखी है। ऐसे में ट्रंप के नए बयान और सैन्य कार्रवाई की अटकलों ने पश्चिम एशिया में एक बड़े टकराव की आशंका को फिर बढ़ा दिया है।

इसाइल का हमास के शीर्ष सैन्य कमांडर को मार गिराने का दावा, 6 अक्टूबर 2023 के हमले का था मास्टरमाइंड

यरुशलम, एजेंसी। इसाइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी में किए गए एक हवाई हमले में हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख नेताओं में शामिल इज्ज अल-दीन अल-हदाद को मार गिराया। इसाइल के मुताबिक हदाद 7 अक्टूबर 2023 को इसाइल पर हुए हमास हमलों की योजना और उसे अंजाम देने वाले प्रमुख रणनीतिकारों में से एक था। इसाइल ने गाजा पट्टी में एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया। इस बार इसाइल के निशाने पर सीधे तौर पर हमास का सबसे बड़ा सैन्य कमांडर था। अब उसकी मौत का खबर साने आ रही है। बताया गया कि उसने यह जिम्मेदारी अपने पूर्ववर्ती को सौंपा और की मौत के बाद संभाली थी। मोहम्मद सिनवार भी इसाइल कमांडरों में मारा गया था। आज हदाद के परिवार ने एसीसिएटेड प्रेस को उसकी मौत की पुष्टि की। इसाइल इसे अपनी सैन्य कार्रवाई की बड़ी सफलता मान रहा है, जबकि क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। हदाद की मौत ऐसे समय में हुई है जब इसाइल और हमास के बीच संघर्षविराम बेहद नाजुक स्थिति में है। हमास के निरस्त्रीकरण समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण युद्धविराम समझौते की प्रगति धीमी पड़ गई है।

